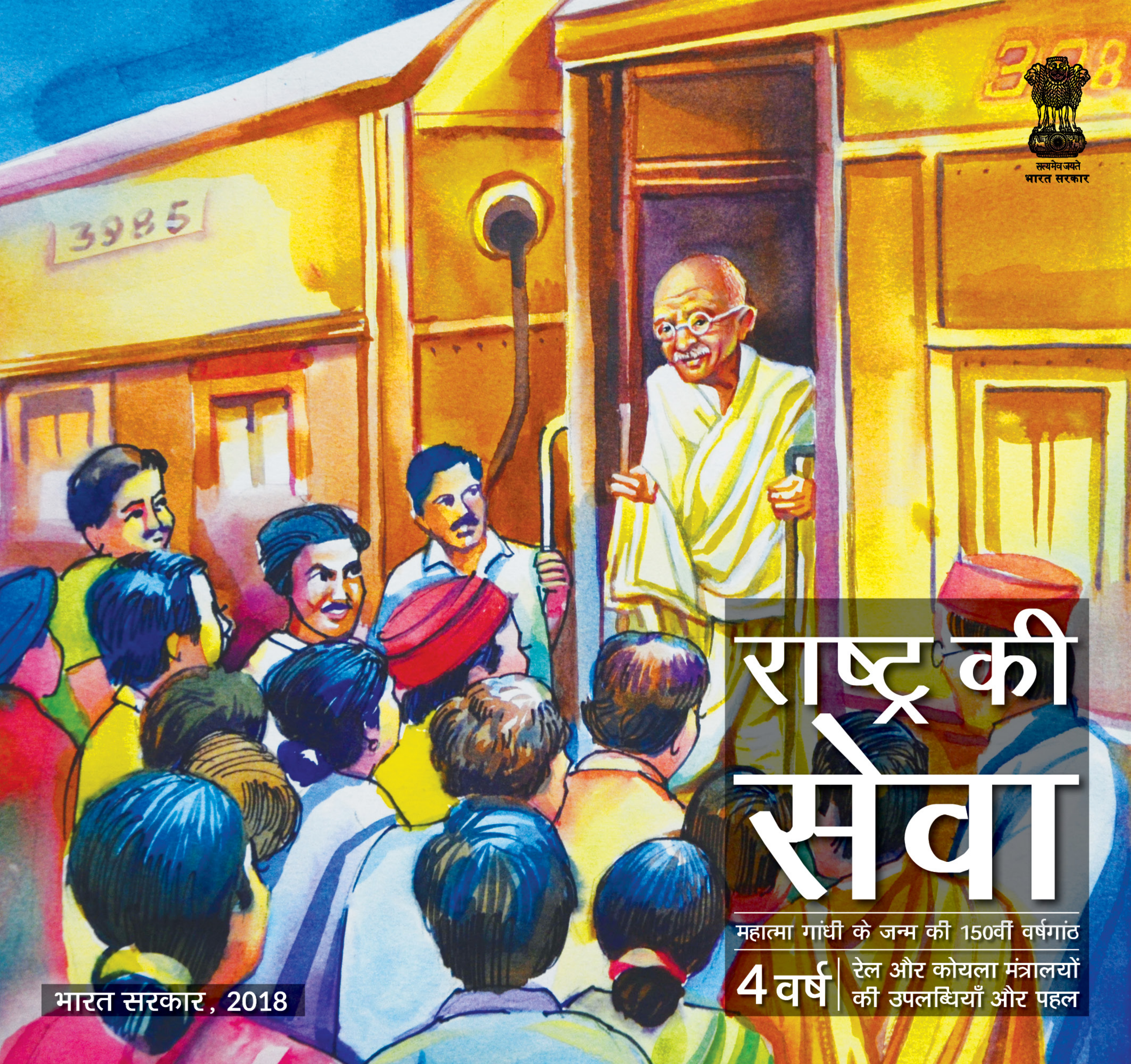

सत्यमेव जयते
भारत सरकार

राष्ट्र की सेवा

महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ

4 वर्ष | रेल और कोयला मंत्रालयों की उपलब्धियाँ और पहल

भारत सरकार, 2018

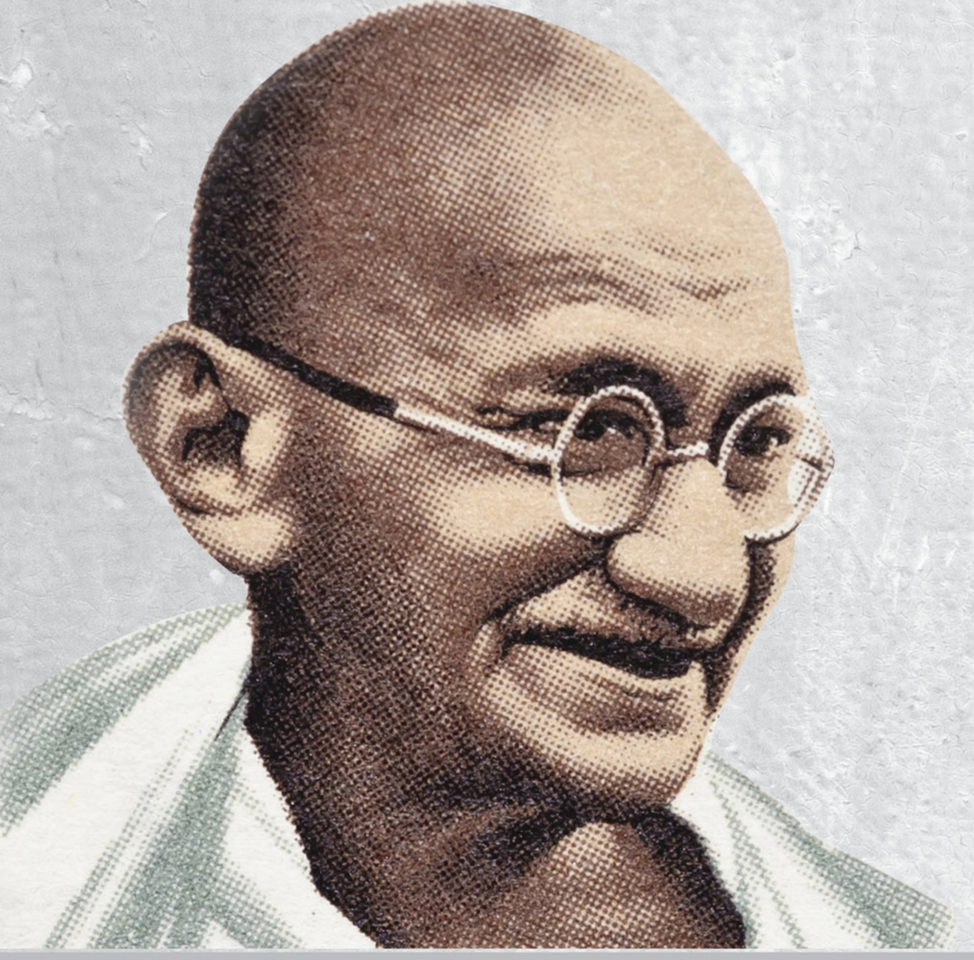

रेल और कोयला मंत्रालय महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ मनाते हुए बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका में ट्रेनों में अनुभवों से लेकर उनके द्वारा भारत में लोगों को जागृत करने तक में रेलवे की भूमिका आज राष्ट्र को याद आती है। जिस तरह गांधी जी ट्रेनों में सफर करते हुए भारत के हर हिस्से से जुड़े, उसी तरह ट्रेन आज भी देश भर के लोगों को देश के हर हिस्से से जोड़ती है।

आज़ादी की लड़ाई के दौरान ट्रेनें और रेलवे स्टेशन हज़ारों भारतीयों की पसंदीदा जगहें बन गए जहाँ वे अपने नेता को देखने और सत्य, अहिंसा और आज़ादी के रास्ते पर उनके साथ चलने के लिए जुटते थे।

न्यू इंडिया की ओर

विज़न 2022

“खुद वो बदलाव बनिये जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं”

– महात्मा गांधी
(1869-1948)

महात्मा गांधी के जिन आदर्शों पर चलकर देश आज़ाद हुआ, उन्हीं आदर्शों से प्रेरित होकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के 75 वें वर्ष–2022 तक न्यू इंडिया के निर्माण का विज़न दिया है। रेल और कोयला मंत्रालय न्यू इंडिया बनाने और देश को प्रगति और समृद्धि के शिखर पर पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

“भारतीय रेल राष्ट्र की विकास यात्रा का इंजन बनेगा”

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

कवर पर प्रदर्शित चित्र महात्मा गांधी का स्मरण कराता है, जिन्होंने स्वतंत्रता और सत्य के संदेश को फैलाने के लिए भारतीय रेलवे पर देश भर में यात्रा की थीं। इसे पी. श्याम सुंदर आचारी द्वारा चित्रित किया गया, जो सामान्य प्रशासन विभाग, ईस्ट कोस्ट रेलवे में कार्यरत हैं।

सुरक्षा सर्वोपरि

“समस्या की सही पहचान ही उसका तीन चौथाई समाधान है”

– महात्मा गांधी

118 — 2013-14

रेल हादसे घट कर हुए **62%**

73 — 2017-18

तेज गति से रेल नवीनीकरण

2013–14 में 2,926 किमी. की अपेक्षा 2017–18 में 4,405 किमी. रेल नवीनीकरण – 50% की वृद्धि

केवल अधिक सुरक्षित एल.एच.बी. कोचों का उत्पादन

सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता

सुरक्षा की दृष्टि से 2017-18 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

1.1 लाख सुरक्षा संबंधी पदों पर भर्ती

सुरक्षा सर्वोपरि

राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (आर.आर.एस.के.)

सुरक्षा व्यय हेतु ₹ 1 लाख करोड़ के कोष का सृजन
अब तक ₹ 16,000 करोड़ खर्च किये गए

फुट ओवर ब्रिज अब सेफ्टी आइटम में शामिल

2009–14 में औसतन प्रतिवर्ष 23 की अपेक्षा 2014–18 में औसतन प्रतिवर्ष 74 फुट ओवर ब्रिज निर्मित – 221% की बढ़ोत्तरी

सेना के साथ मिलकर कार्य

मुम्बई के एलफिंस्टन रोड–परेल, करी रोड एवं अम्बीवली स्टेशनों पर सेना की सहायता से तीन फुट ओवर ब्रिज का निर्माण

सभी स्टेशनों एवं ट्रेनों में सी.सी.टी.वी./वीडियो सर्विलान्स प्रणाली स्थापित की जा रही है

अब तक के सर्वाधिक रोड ओवर ब्रिज/रोड अण्डर ब्रिज/सब–वे का निर्माण

औसत प्रतिवर्ष निर्माण में 3 गुनी वृद्धि

पिछले 4 वर्षो में 5,479 मानवरहित रेलवे फाटक समाप्त किये गये

जून, 2018 तक प्रमुख रेल मार्गों पर सभी मानवरहित रेलवे फाटक समाप्त कर दिए जाएंगे

पूंजीगत व्यय में अभूतपूर्व वृद्धि

2009–14 की अपेक्षा 2014–19 में दोगुने से अधिक औसत वार्षिक पूंजीगत व्यय

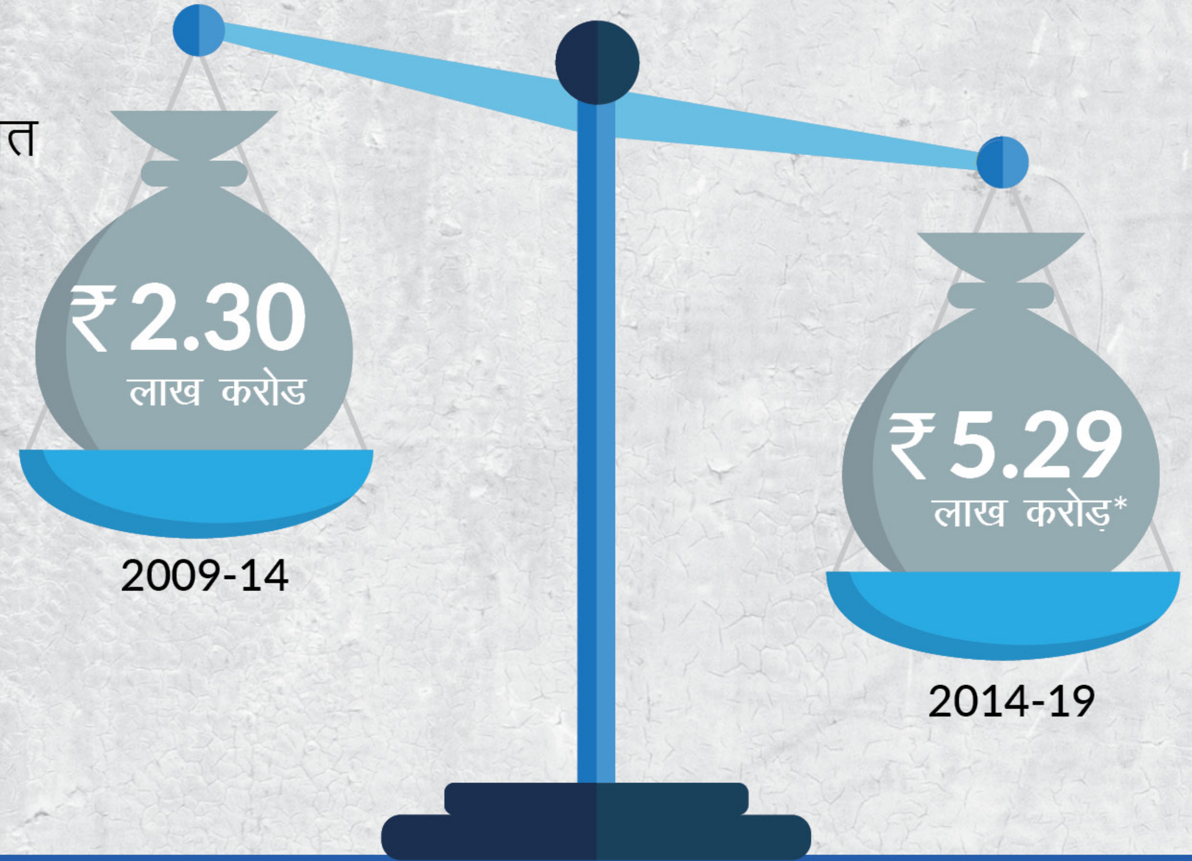

* बजट अनुमान 2018–19 सहित

"मनुष्य अपना भाग्य खुद बनाता है। इसलिए मैं आपसे खुद अपना भाग्य बनाने का आग्रह करता हूँ"

– महात्मा गांधी

क्षमता वृद्धि

भविष्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण

रेल लाइनों की कमीशनिंग में तेज़ी

नई लाइन/दोहरीकरण/तीसरी एवं चौथी लाइन निर्माण परियोजनाओं की औसत कमीशनिंग दर 4.1 किमी. प्रति दिन (2009–14) से 59% बढ़कर 6.53 किमी. प्रति दिन (2014–18)

4.1 किमी. प्रति दिन (2009-14)

6.53 किमी. प्रति दिन (2014-18)

भारत को जोड़ने की पहल एक्ट ईस्ट नीति

पूर्वोत्तर में संपूर्ण रेल नेटवर्क ब्रॉड गेज में परिवर्तित

जिरीबाम–इम्फाल नई रेल लाइन परियोजना के अन्तर्गत विश्व के सबसे ऊँचे पुलों में से एक का निर्माण जारी

मेघालय (दुधनोई–मेंदीपाथर), त्रिपुरा (कुमारघाट–अगरतला) एवं मिजोरम (कथकल–भैरबी) के साथ रेल सम्पर्क स्थापित

₹ 51,428 करोड़ की लागत वाली 1,397 किमी. लम्बी रेल परियोजनाएं प्रगति पर

उपनगरीय नेटवर्क पर विशेष जोर

बजट 2018–19 में ₹ 17,000 करोड़ की लागत से बेंगलुरू उपनगरीय नेटवर्क का विकास

लगभग 15 लाख दैनिक यात्रियों को लाभ

वातानुकूलित कोचों वाली आधुनिक प्रणाली, अत्याधुनिक सिग्नलिंग और नए स्टेशन

बजट 2018–19 में ₹ 54,777 करोड़ की लागत से मुम्बई उपनगरीय प्रणाली में सुधार

नए कॉरिडोर, अतिरिक्त लाइनें / विस्तार एवं बेहतर सिग्नलिंग

वातानुकूलित कोचों एवं विकसित स्टेशनों से यात्री सुविधा में वृद्धि

भारत की पहली बुलेट ट्रेन

मुम्बई–अहमदाबाद हाई स्पीड रेल

एक मिनट से कम देरी के रिकॉर्ड वाली शिंकानसेन तकनीक – 50 सालों में कोई भी हताहत नहीं

यात्रा समय में कमी – लगभग 8 घंटे से 2 घंटे

जापान सरकार द्वारा बहुत कम ब्याज दर पर निधि की उपलब्धता इसे वहन योग्य बनाती है

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के बड़े अवसर

'मेक इन इंडिया' से भारत हाई स्पीड तकनीक में अग्रणी बनेगा

"जीवन एक अभिलाषा है जिसका उद्देश्य पूर्णता को प्राप्त करना है और यही आत्मबोध है।"

– महात्मा गांधी

मेक इन इंडिया

बिहार के मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाना

हल्दिया में डीज़ल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (डेमू) रेक उत्पादन कारखाना

आगामी परियोजनाएं

मराठवाड़ा के लातूर में उपनगरीय एवं मेट्रो ट्रेनों के लिये कोच निर्माण कारखाना

असम के न्यू बोंगाईगांव में एल.एच.बी. कोचों के नवीनीकरण हेतु कारखाना स्वीकृत

असम के लमडिंग में डेमू/मेनलाइन ईएमयू शेड स्वीकृत

बुंदेलखंड के झाँसी और हरियाणा के सोनीपत में कोच नवीनीकरण कारखानों की योजना

“अपने साथियों के प्रति की गई भलाई ही इंसान की सच्ची दौलत है”

– महात्मा गांधी

विद्युतीकृत रेलवे

किसी एक वर्ष में अब तक का सर्वाधिक विद्युतीकरण

4,087 रूट किमी.
(2017-18)

छः गुना से
अधिक बढ़ोत्तरी

610 रूट किमी.
(2013-14)

विद्युतीकरण में
अभूतपूर्व वृद्धि

गति

विश्व में पहली बार लोकोमोटिव का डीजल से
विद्युत ट्रैक्शन में बदलाव

5 हजार हार्स पावर का नया स्वदेशी विद्युत लोकोमोटिव
– पुराने स्वरूप से 92% अधिक शक्तिशाली

मालगाड़ियों की बेहतर ऊर्जा दक्षता व गति के लिये नई पीढ़ी
के 12 हजार हार्स पावर क्षमता के लोकोमोटिव का निर्माण

बचत

ऊर्जा दक्षता से ईंधन खर्च में कमी

पूर्ण विद्युतीकरण से लगभग ₹13,500 करोड़ की सालाना
बचत अपेक्षित

भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान एवं
व्यापार घाटे में सुधार

सस्टेनेबिलिटी

कार्बन उत्सर्जन में कमी एवं
सस्टेनेबल पर्यावरण को बढ़ावा

नई रेल, नई सिग्नलिंग

भारतीय रेलों पर आधुनिक सिग्नलिंग प्रणालियाँ अपनाई जाएंगी

2017-18 में सिग्नलिंग प्रणाली को सुधारने हेतु ₹1,299 करोड़ का निवेश

पिछले वर्ष की तुलना में 31% अधिक

2017-18 में 208 स्टेशनों पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इन्टरलॉकिंग प्रणाली लगाई गई

पिछले वर्ष की तुलना में 26% अधिक

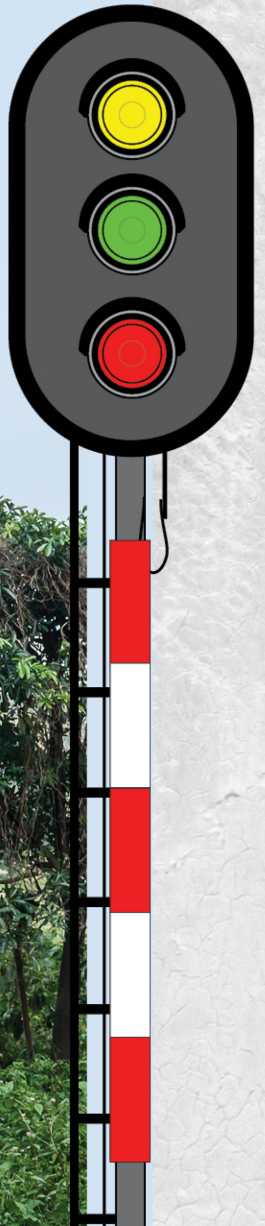

भारतीय अर्थव्यवस्था का वाहक: मालभाड़ा

2022 तक मालभाड़ा यातायात में बाजार हिस्सेदारी 33% से बढ़ाकर 45% करने का लक्ष्य

इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं मालभाड़ा यातायात के संचालन में निजी भागीदारी को बढ़ावा

प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल (पी.एफ.टी.) नीति – अब तक 58 पी.एफ.टी. अधिसूचित

वैगनों में निजी निवेश को बढ़ावा देने वाली नीति जारी

2013-14 के 1,052 मिलियन टन की अपेक्षा 2017-18 में 1,162 मिलियन टन मालभाड़ा लदान – अब तक का सर्वश्रेष्ठ, 10.5% की वृद्धि

2017-18 में मालभाड़ा द्वारा ₹ 1.17 लाख करोड़ की प्रत्याशित आय–अब तक की सर्वाधिक, पिछले वर्ष से 12% अधिक

भारतीय अर्थव्यवस्था का वाहकः डी.एफ.सी.

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डी.एफ.सी.)

2,822 किमी. लम्बे पश्चिमी व पूर्वी डी.एफ.सी. की 2019-20 तक चरणों में कमीशनिंग

मार्च, 2014 तक आवंटित ₹ 12,749 करोड़ के ठेकों की अपेक्षा पिछले 4 वर्षों में ₹ 39,157 करोड़ के ठेके आवंटित (200% से अधिक की वृद्धि)

माल यातायात के यात्रा समय व ढुलाई लागत में कमी और मौजूदा नेटवर्क पर कम दबाव

कारखानों एवं फार्मों को बन्दरगाहों से जोड़ने से आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन

आर्थिक विकास के केन्द्रों का सृजन

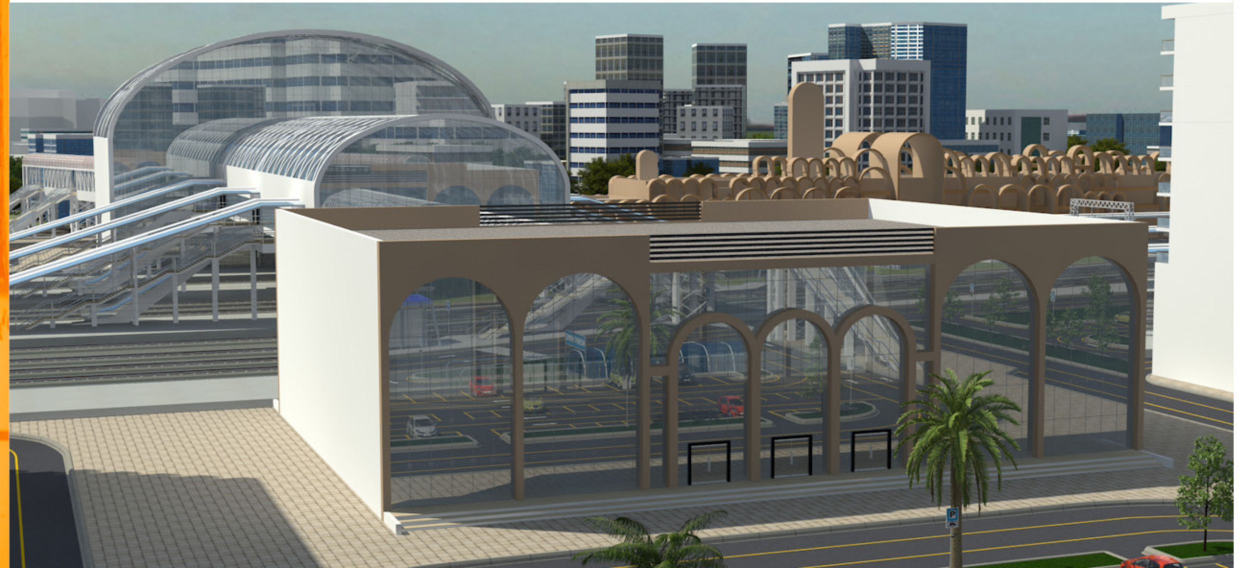

“स्वछता भक्ति के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है”

– महात्मा गांधी

स्टेशन विकास

भविष्य की ओर एक छलांग

विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त स्टेशनों का विकास

यात्रियों हेतु बेहतर सुविधाओं के लिये स्टेशनों का पुनर्वर्गीकरण

आय, यात्री आवागमन, स्ट्रैटेजिक महत्व को ध्यान में रखते हुए अधिक वस्तुनिष्ठ मानदंड

मार्च, 2019 तक रेलवे द्वारा 68 स्टेशनों का सुधार

स्थानीय कला के द्वारा अब तक 60 स्टेशनों का सौन्दर्यीकरण

मध्य प्रदेश के हबीबगंज व गुजरात के गांधीनगर स्टेशनों का दिसम्बर, 2018 तक पुनर्विकास

सभी रेलवे स्टेशन 100% एल.ई.डी. लाइटों से प्रकाशित

अविस्मरणीय यात्रा

यात्री कोचों में सुधार

मार्च, 2019 तक, मेल/पैसेंजर ट्रेनों के 5,000 कोचों में आंतरिक सुधार

आधुनिक ट्रेनें/कोच

पहले स्वदेशी ट्रेन–सेट की इस वर्ष कमीशनिंग

तेजस, अन्त्योदय एवं हमसफर ट्रेनें आरम्भ

डबल डेकर उदय रेक सेवा हेतु तैयार

आधुनिक विशिष्टताओं युक्त दीनदयालु एवं अनुभूति कोच

पर्यटकों द्वारा सुन्दर दृश्यों का आनन्द लेने हेतु चुने हुए मार्गों पर पारदर्शी छत वाले 'विस्टाडोम' कोच

यात्री सेवाओं में बढ़ोत्तरी

नई ट्रेनें

पिछले 4 वर्षों में 407 नई ट्रेन सेवाएं

पर्वों के दौरान मांग को पूरा करने हेतु पिछले 4 वर्षों में 1.37 लाख ट्रेन सेवाएं

रोलिंग स्टॉक के बेहतर उपयोग, परिसंपत्तियों के दोहन और पड़ाव अवधि के उपयोग से 22 नई ट्रेनें एवं 44 ट्रेनों का विस्तार

थर्ड पार्टी द्वारा जांच

100 गुप्त ग्राहकों द्वारा यात्री सुविधाओं, खानपान, स्वच्छता व समयपालन की निगरानी

समयपालन

इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सुरक्षा कार्यों को दी जा रही प्राथमिकता के कारण अल्पावधि में समयपालन प्रभावित

परन्तु, दीर्घावधि में इससे तीव्र और सुरक्षित ट्रेन परिचालन संभव हो सकेगा

परिचालन समय में कमी व योजनाबद्ध मेंटेनेन्स ब्लॉक से ट्रेनों की बेहतर टाइम टेब्लिंग

यात्रियों को ट्रेनों की देरी की सूचना देने हेतु 1,373 ट्रेनों में एस.एम.एस. सेवा प्रारम्भ

विश्वस्तरीय यात्री सुविधाएं

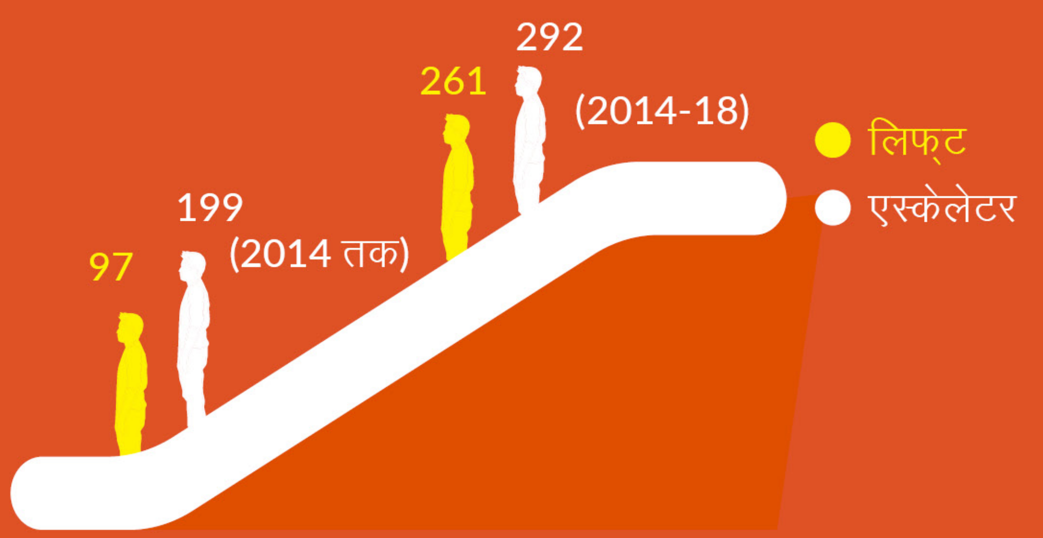

एस्केलेटर एवं लिफ्ट

सुविधाजनक यात्री आवागमन में सहायक

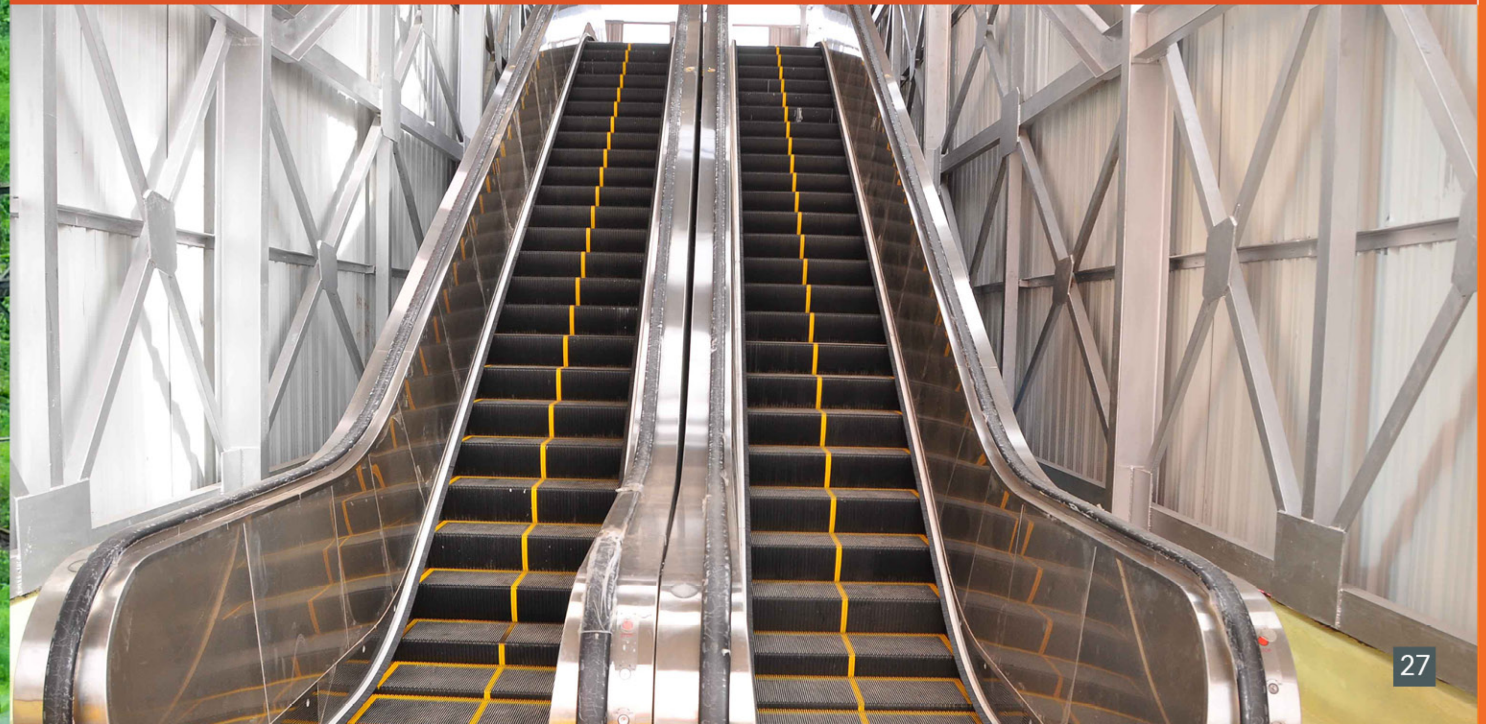

डिजिटल भारत, डिजिटल रेल

675 से अधिक स्टेशनों पर हाई स्पीड वाई–फाई सेवा

सभी स्टेशनों पर वाई–फाई सेवा उपलब्ध होगी

स्टेशन के नजदीकी इलाकों के युवा, महिलाएं, किसान व ग्रामीण होंगे लाभान्वित

कैशलेस लेन–देन हेतु प्वाइंट ऑफ सेल (पी.ओ.एस.) मशीनें

लगभग 4,000 स्थानों पर 9,100 पी.ओ.एस. मशीनें

'नो बिल, फ्री फूड' नीतिः अनिवार्य बिलिंग हेतु पी.ओ.एस. मशीनें

ई–टिकटिंग की क्षमता 2014 में 2,000 टिकट प्रति मिनट से बढ़ाकर 2018 में अनुमानित 20,000 टिकट प्रति मिनट

बुकिंग काउन्टरों पर क्रेडिट और डेबिट कार्डों द्वारा खरीदी गई टिकटों पर सर्विस चार्ज हटाया गया

सोशल मीडिया के द्वारा यात्री शिकायतों का रियल टाइम समाधान

खानपान

2017–18 में अब तक 16 बेस किचनों में सुधार

बेस किचनों में गुणवत्ता और स्वच्छता को सुधारने के लिए 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' द्वारा खाने की तैयारी पर निगरानी

314 स्टेशनों पर ई–केटरिंग प्रारम्भ व 100 और स्टेशनों की योजना। 7,000 से अधिक थालियां प्रतिदिन

300 से अधिक ट्रेनों में सभी खाद्य सामग्रियों पर एम.आर.पी. छापना अनिवार्य

रेलवे में टिप मांगने पर रोक

32 राजधानी, शताब्दी, दुरन्तो एवं गतिमान ट्रेनों में केटरिंग सुविधा वैकल्पिक बनाई गई

600 स्टेशनों पर 1,689 वॉटर वेंडिंग मशीनें

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छता ही सेवा

488 स्टेशनों पर एकीकृत मशीनी साफ–सफाई की व्यवस्था

मार्च, 2019 तक सभी उपनगरीय एवं बड़े स्टेशनों पर मशीनों द्वारा साफ–सफाई

धुले हुए लिनेन की गुणवत्ता में सुधार के लिये मशीनीकृत लॉण्ड्रीः 2009–14 में 26 की अपेक्षा 2014–18 में 33 की व्यवस्था

दिसम्बर, 2019 तक धुले हुए लिनेन की गुणवत्ता में सुधार हेतु 100% मशीनीकृत लॉण्ड्री

लक्ष्य से अधिक बायो–टॉयलेट

स्थापित बायो–टॉयलेटः 2004–14 में 9,587 की अपेक्षा 2014–18 में 1,17,164

मार्च, 2019 तक सभी ट्रेनों में बायो–टॉयलेट। हवाई जहाजों की तर्ज पर वैक्यूम बायो–टॉयलेट का परीक्षण

दिसम्बर, 2018 तक बड़े स्टेशनों पर सस्ती दरों वाली सैनिटरी पैड डिस्पेंसिंग मशीनें

रेलवे ट्रैक की स्वच्छता

दिल्ली में ऑटोमेटिक रेल–माउन्टेड मशीन द्वारा कूड़े की सफाई शुरू। पूरे भारत में ऐसी मशीनें लगाने की योजना

स्वतंत्र थर्ड पार्टी सर्वेक्षण

स्टेशनों व ट्रेनों में स्वतंत्र थर्ड पार्टी सर्वेक्षण प्रारम्भ

हाउसकीपिंग ठेकों हेतु नई प्रणाली

ठेकेदारों को भुगतान यात्रियों द्वारा दी गई रेटिंग पर भी आधारित

बदलाव के लिये सुधार: पारदर्शिता एवं जवाबदेही

सेवा संबंधी ठेकों की सामान्य शर्तें जारी

प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और लागत में बचत हेतु सेवा ठेकेदारों के लिये आसान पंजीकरण प्रक्रिया

खरीद प्रक्रिया में बदलाव

ई–रिवर्स नीलामी नीति जारी
₹ 20,000 करोड़ की वार्षिक बचत में सहायक होगी

एकल वेब–पोर्टल द्वारा 100% ई–प्रोक्योरमेन्ट
ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल द्वारा लगभग 17 लाख ई–निविदाएं जारी

2014 में आई.आर.ई.पी.एस. पोर्टल पर पंजीकृत 19,867 वेण्डरों की अपेक्षा 2018 में 81,127 वेण्डर – 4 गुनी वृद्धि

जी.ई.एम.(गवर्नमेन्ट ई–मार्केटप्लेस) के माध्यम से सामान्य उपयोग की वस्तुओं/सेवाओं का प्रोक्योरमेन्ट अनिवार्य

वेण्डरों की संख्या में वृद्धि एवं लागत में कमी से प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन

रेलवे द्वारा ठेकेदारों को 'फर्स्ट इन फर्स्ट आउट' की प्रणाली पर भुगतान

सभी आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को, लेटर ऑफ क्रेडिट की सुविधा द्वारा, वर्किंग केपिटल प्राप्त करने में सहायता

रेलवे में रसीदी नोट, आपूर्तिकर्ता बिल व रसीदी चालानों का डिजिटलीकरण

इसके अन्तर्गत लगभग ₹50,000 करोड़ के रसीदी नोट, रसीदी चालान

"सुधार से जागृति आती है। वास्तव में जागृत होने पर राष्ट्र केवल एक क्षेत्र में सुधार से संतुष्ट नहीं होगा"

– महात्मा गांधी

GeM
Government
e Marketplace

अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आर.डी.एस.ओ.) में सरलीकृत अनुमोदन प्रक्रियाएं

नामित एजेंसियों (आर.डी.एस.ओ. उत्पादन इकाइयों इत्यादि) द्वारा अनुमोदित वेण्डरों का विवरण ऑनलाइन उपलब्ध

प्रक्रिया समयसीमा 30 महीने से घटाकर 6 महीने की गयी

13 लाख से अधिक रेलकर्मियों का परिवार

फील्ड अधिकारियों का सशक्तिकरण

कार्यों के अनुमोदन के लिए महाप्रबंधकों को अधिकतम सीमा तक शक्तियां प्रदान की गईं

त्वरित प्रक्रिया और निर्णय हेतु मंडल रेल प्रबंधकों का सेवा ठेकों की शक्तियां प्रदान की गईं

वेंडर अनुमोदन के विकेन्द्रीकरण द्वारा उत्पादन इकाइयों का उनके स्रोतों के विकास और प्रबंधन हेतु सशक्तिकरण

> **"आपको इंसानियत में भरोसा नहीं खोना चाहिए। इंसानियत एक सागर की तरह है जिसकी कुछ बूंदें अगर गंदी हो जाएं तो भी सागर गंदा नहीं होता"**
>
> **– महात्मा गांधी**

कर्मचारी कल्याण में सुधार

लोको पायलट, गार्ड, टी.टी.ई. जैसे कर्मचारियों हेतु रनिंग रूम में सुधार

कर्मचारी कॉलोनियों व कार्यस्थलों इत्यादि में सुधार

बेहतर आवासीय सुविधा के लिये रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) बैरकों का अपग्रेडेशन

सभी कर्मचारियों की वार्षिक चिकित्सा जांच (आर.पी.एफ. हेतु वर्ष में दो बार)

खेलों में भारत का गौरव

भारत द्वारा जीते गए कुल अंतर्राष्ट्रीय पदकों में से लगभग 33% रेलवे के खिलाड़ियों ने दिलाए

राष्ट्रमंडल खेल, 2018 में कुश्ती एवं भारोत्तोलन (वेटलिफ्टिंग) में भारत द्वारा जीते गये सभी 10 स्वर्ण पदक रेलवे के खिलाड़ियों ने दिलाए

ओलम्पिक 2016 में साक्षी मालिक ने कांस्य पदक जीता

मीराबाई चानू

कुशल कार्यबल का निर्माण

वड़ोदरा में भारत का प्रथम राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय

- कुशल मानव संसाधन के स्रोत का निर्माण
- उत्पादकता में वृद्धि एवं 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहन
- भारतीय रेल आधुनिकीकरण के मार्ग पर अग्रसर
- अगस्त, 2018 में 2 पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे – बी.बी.ए. (परिवहन प्रबन्धन) व बी.एस.सी. (परिवहन तकनीक)
- 2019 से स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएट) पाठ्यक्रम प्रारम्भ होने की संभावना
- नवीनतम शिक्षा प्रणाली व तकनीकी उपयोग के माध्यम से बेहतर कार्य दक्षता और उत्पादकता

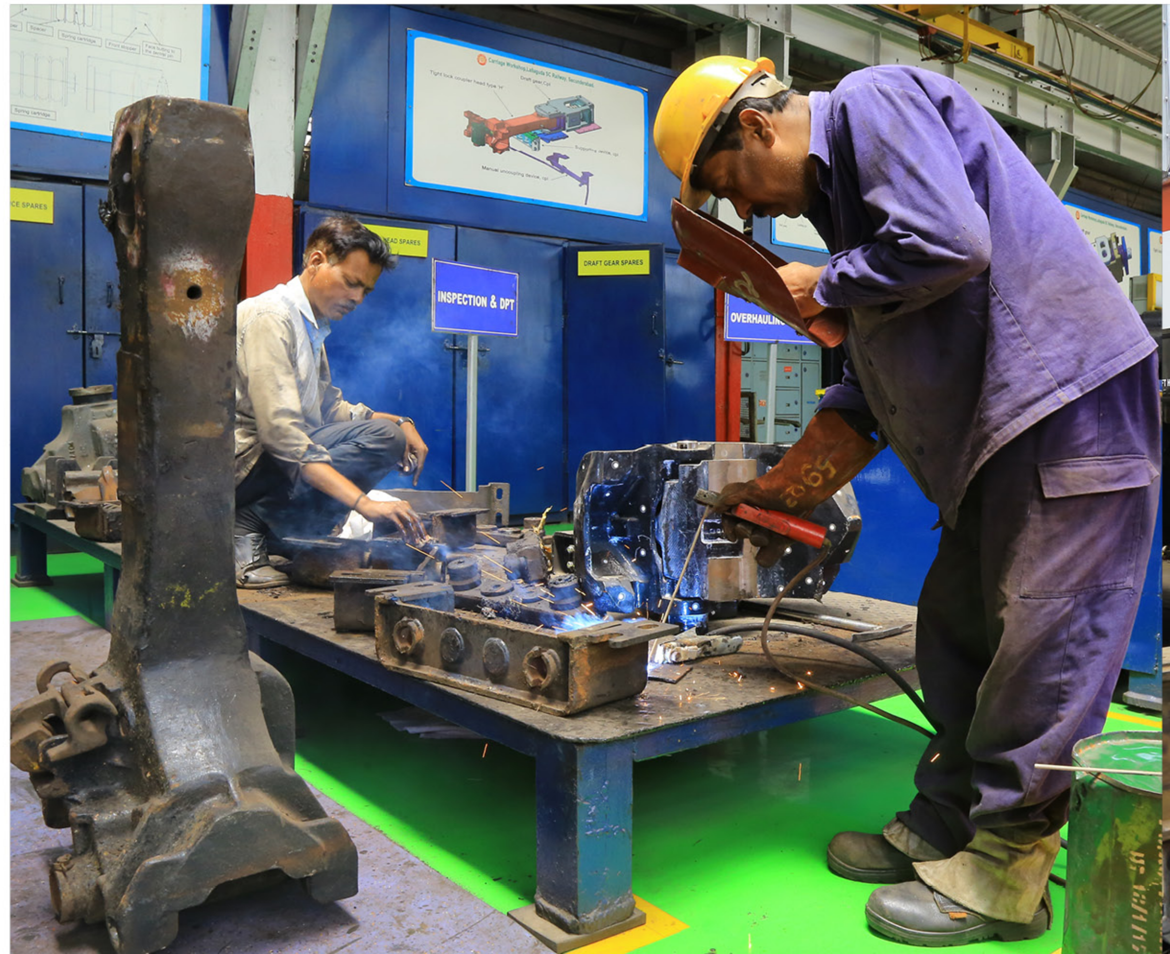

प्रोजेक्ट सक्षम

सभी कर्मचारियों को 5 दिन का कार्य स्थल पर/क्लास रूम में प्रशिक्षण

प्रशिक्षुओं (अप्रेन्टिस) का प्रशिक्षण

- रेलवे द्वारा प्रतिवर्ष, कुल कर्मचारी संख्या के 5% के बराबर, प्रशिक्षुओं को कौशल प्रशिक्षण
- प्रशिक्षुओं की संख्या लगभग 20,000 से बढ़ाकर 31,000 की गई

कोयलाः
राष्ट्र के विकास का ईंधन

कोयले की खोज हेतु लगभग दोगुनी ड्रिलिंगः 2013-14 में 6.9 लाख मीटर की अपेक्षा 2017-18 में 13.7 लाख मीटर

गत 4 वर्षों में कोल इंडिया के उत्पादन में 105 मिलियन टन की वृद्धि हुई, जो 2013-14 से पहले 7 वर्षों में हुई थी

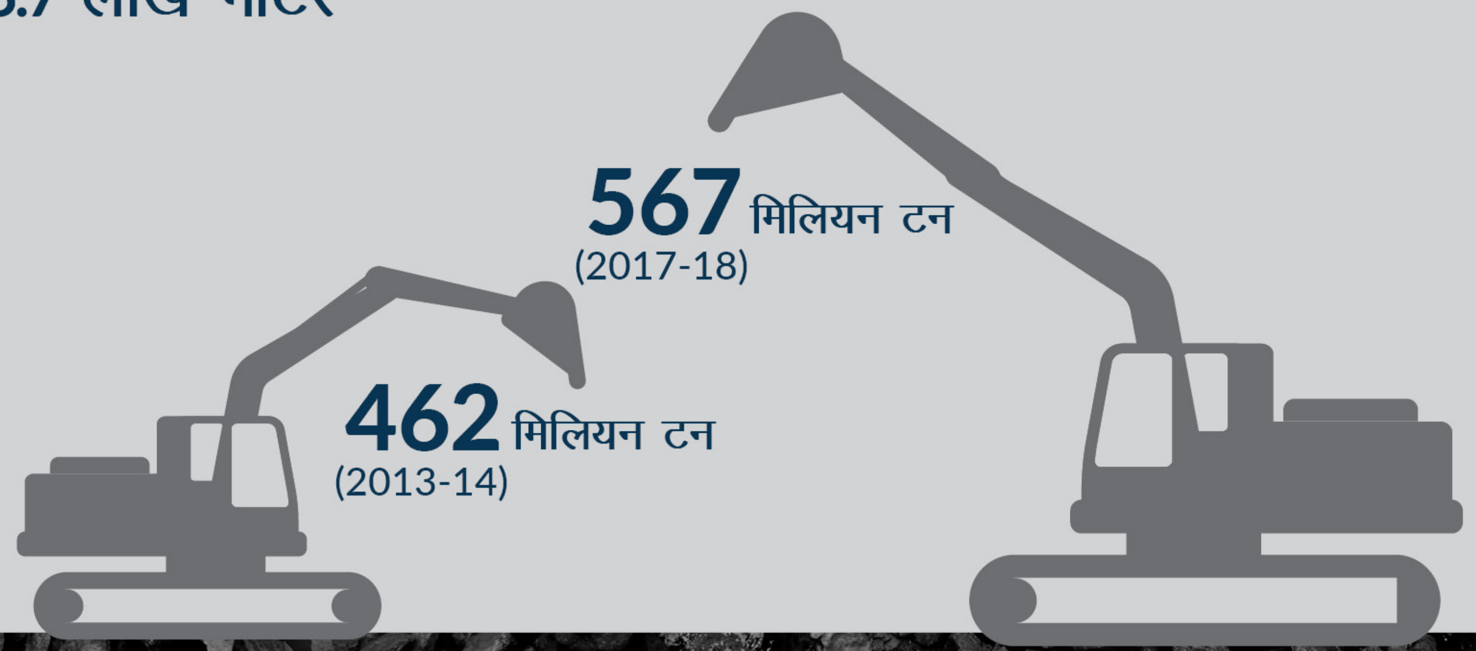

कोल इंडिया के कोयला ऑफटेक में 23% की वृद्धि

"धरती इंसान की हर जरूरत को पूरा कर सकती है लेकिन उसके लालच को नहीं"

– महात्मा गांधी

बेहतर गुणवत्ता युक्त कोयला

कोयले की गुणवत्ता की जांच के लिए थर्ड पार्टी सैम्पलिंग प्रकिया

पावर प्लान्टों को 100% क्रश्ड कोयला

कोल इंडिया व सिंगरेनी कोलरीज़ कम्पनी की सभी खदानों का रीग्रेडेशन

विद्युत लागत में कमी

विगत 4 वर्षों में प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन में लगने वाले कोयले (स्पेसिफिक कोल कन्ज़म्पशन) की मात्रा में 8% की कमी

"यदि मुझे विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ तो इसे करने की क्षमता अवश्य ही प्राप्त कर लूंगा, चाहे प्रारम्भ में मुझ में यह क्षमता न रही हो"

– महात्मा गांधी

न्यू इंडिया हेतु कोयला सुधार

व्यवसायिक कोयला खनन

1973 के राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला खनन का सबसे महत्वाकांक्षी सुधार

कोयला आयात पर निर्भरता में कमी आएगी एवं सुनिश्चित कोयला आपूर्ति से ऊर्जा सुरक्षा निश्चित होगी

बढ़े हुए निवेश से परोक्ष एवं अपरोक्ष रोजगार का सृजन

पारदर्शी ई–नीलामी से कोयला ब्लॉक आवंटन

89 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी एवं आवंटन

कोयला उत्पादक राज्यों को 100% राजस्व

पारदर्शिता एवं जबाबदेही

कोयला लिंकेज का रैश्नलाइजेशन

55.66 मिलियन टन कुल कोयला मूवमेन्ट के रैश्नलाइज़ेशन से ₹ 3,359 करोड़ की संभावित वार्षिक बचत

शक्ति

(स्कीम फॉर हार्नेसिंग एण्ड ऐलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेन्ट्ली इन इंडिया)

कोयला लिंकेज की नीलामी एवं आवंटन हेतु परिवर्तनकारी नीति

सस्ती ऊर्जा और पारदर्शी कोयला आवंटन

'शक्ति' के अन्तर्गत 16 ईंधन आपूर्ति समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए

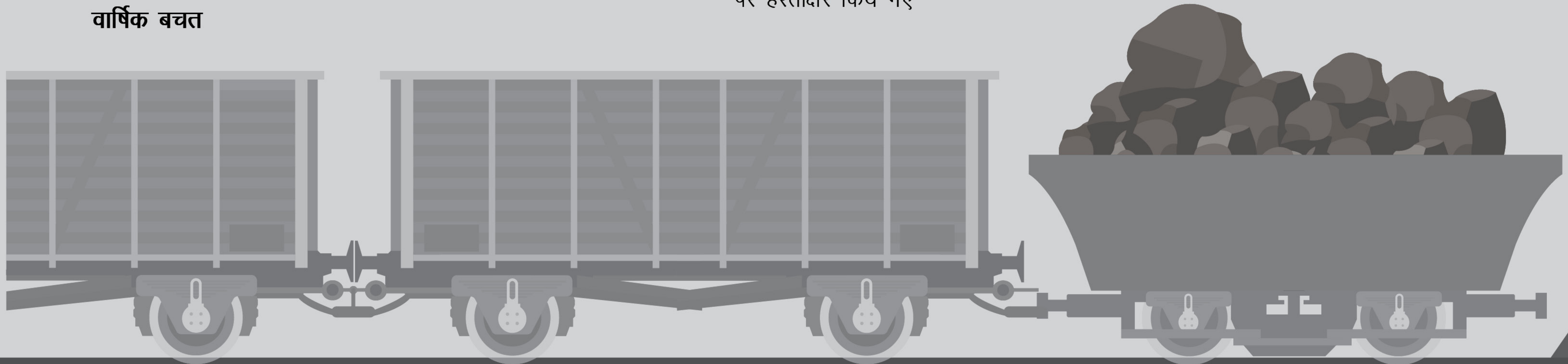

रेल कोयला सहभागिता

कोयला परिवहन को बढ़ाने के लिये कोयला निकासी की 14 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समयसीमा निर्धारित

बहुप्रतीक्षित टोरी – शिवपुर नई रेल लाइन (44 किमी.) का टोरी – बालूमाथ रेल खण्ड 9 मार्च, 2018 से शुरू

उड़ीसा में झारसुगुड़ा – बारापल्ली (53 किमी.) रेल लाइन पूर्ण

कुल कोयला लदान में वृद्धि

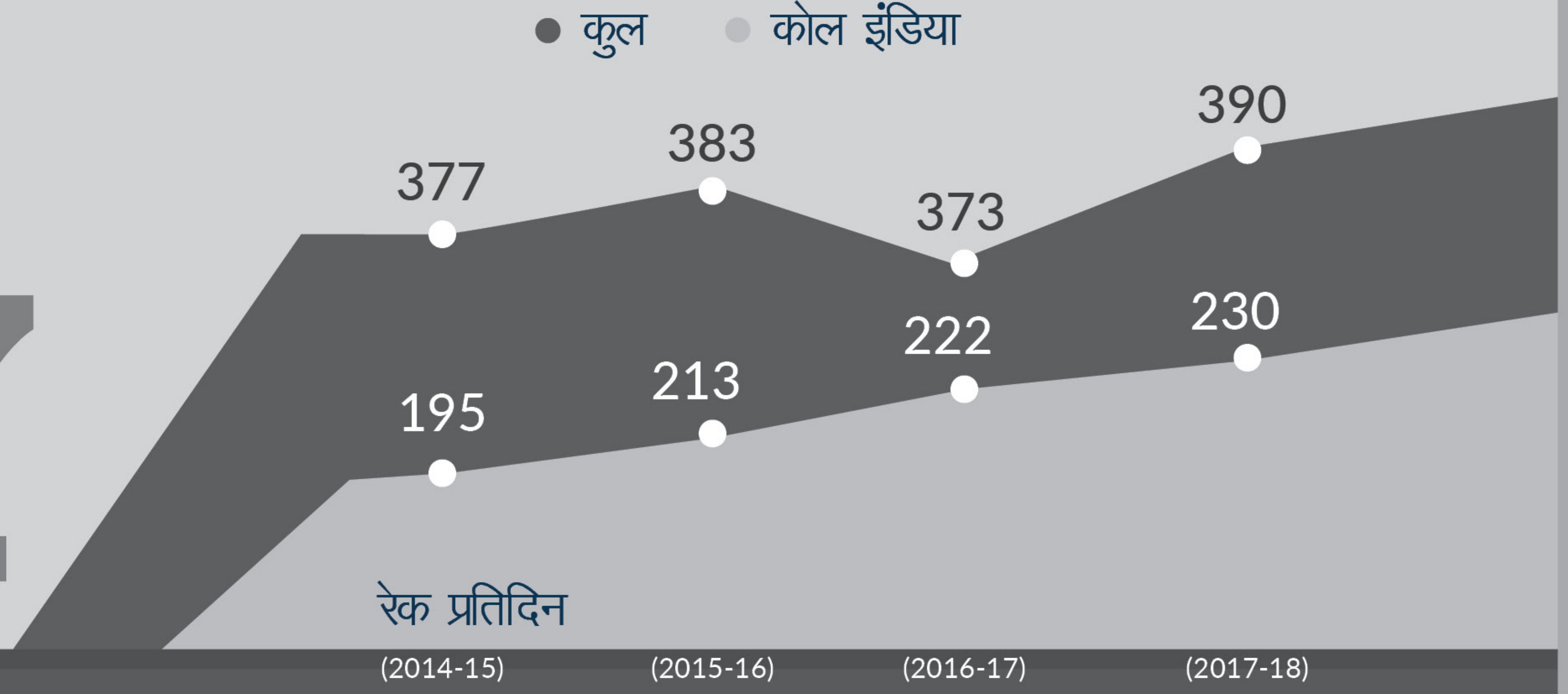

“दूसरों की सेवा में स्वयं को
समर्पित करना स्वयं को जानने
का सर्वोत्तम उपाय है ”

—महात्मा गांधी

सत्यमेव जयते
भारत सरकार